†**شری محمد سلیم:** مہودے۔کینسر جان لیوا بیماری ہے۔ یہ سب لوگ بول رہےہیں لیکن پریونٹیو اریجمنٹ بھی کرنا چاہئے۔ اریڈیکشن کا۔کنٹرول کا مطلب ہے "پریونیٹو " جو تمباکو چوونگ ہوتا ہے پان بہار پان مسالہ آدی۔ اس سرکار کے آتے ہی اخبار میں یہ نیوز آئی ا سے بین کر دیا جائے گا۔ اس دن سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ "اورل کینسر" ہوتا ہے اسلئے پان مسالہ آدی کو۔ میں برانڈ کا نام نہیں بول رہا ہوں۔ ا سے پرموٹ کیا جائے گا۔ لیکن میرے پاس خبر ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ جو ویوسائے کرنے والے لوگ ہیں۔کروڑوں کا ویوسائے ہوتا ہے۔ وہ سب دہلی پہچے اور دوسرے دن سے ہیلتھ منسٹری نے اس بات کو ڈھک دیا کہ یہ بین نہیں ہونے والا ہے۔ کیا کارن ہےکہ ایک مہینہ پہلے آپکا منترالیہ یہ کہہ رہا تھا کہ پان پراگ پان مسالہ سے کینسر ہوتا ہے اسلئے اسکو بین کرنا پڑےگا۔ ان لوگوں سے آپکی کیا بیٹھک ہوئی۔کیا فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن سے آپنے اس بات کو دبا دیا۔کیا اب آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ پان پراگ پان مسالہ سے کینسر ہو سکتا ہے۔ کینسر کی روک تھام کیلئے کیا آپ اس پر پابندی لگائینگے۔ اور کب لگائینگے۔

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI DALIT EZHILMALAI: So far as the question of Pan Masala and Gutkha is concerned, Sir, we have set up a committee in the Ministry itself. They are investigating this issue. We'are not going to be cowed down by any delegation. The Health Ministry has made a policy in this regard. This matter is not concerned with the Health Ministry only. This matter is concerned with three or four Ministries. An inter-Ministerial meeting will be convened very soon. After that we will be able to finalise it. We have constituted a committee in our Ministry.

SHRI SB. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, it is a very simple question of not getting a utilisation certificate from the State Government and diverting funds for any other purpose. Since the hon. Minister is new, I don't want to put a number of questions to him. But Shri Ish Dutt Yadav said that there was a report of the Public Accounts Committee in which it had been stated that there was a total, misappropriation of funds. In spite of that, if the officers have not supplied this information, will the hon. Minister try to go deep into the matter and find out if there is misappropriation or misutilisation of funds'.'

SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, there is no report of misutilisation or misappropriation of funds. It is true that we have not received the utilisation certificate.

MR. CHAIRMAN: But he has asked something else. He has referred to the report of the Public Accounts Committee. Have you seen it?

SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, there is no mention of misutilisation or misappropriation in the Committee report.

SHRI S.B. CHAVAN: It will be better if you go through the report and find it out.

SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, we will look into the matter.

MR. CHAIRMAN: Question No. 42.

*42. [The questioner (Shri Dilip Singh Judev) was absent. *For answer,* vide col. 32 in*fra.]*

रेलवे में परिवहन व्यय की तुलना में प्रकाशित व्यय

*43. **श्री सिंह रामूवालिया**: †

श्री विजेन्द्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ीयों के परिचालन हेतु ईधन पर किया जाने वाला व्यय, रेलवे पर व्यय की

†~~सभा~~ में यह प्रश्न श्री बलवन्न सिंह रामूवालिया द्वारा पूछा गया।

जाने वाली राशि की मात्रा 22 प्रतिशत ही होती है, जबकि इसका प्रशासनिक व्यय 54 प्रतिशत है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है:

(ग) क्या प्रशासनिक व्यय के औचित्य के संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है: और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क)जी नहीं।

(ख)रेलों द्वारा गाड़ीयों के परिचालन के लिए ईधन पर किया गया खर्च, साधारण संचालन व्यय (पेंशन को छोड़कर) के अंतर्गत किए गए कुल खर्च का, लगभग 22% है। प्रशासनिक खर्च अर्थात, प्रबंधन और कार्यालयों में स्थापना पर होने वाला खर्च केवल 8% है । प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 54% के आंकड़े में 8% प्रशासनिक खर्च के अलावा रेल परिसंपत्तियों के अनुसरक्षण तथा गाड़ीयों के परिचालन कार्य में बड़ी संख्या में लगे कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते तथा संबंधी लाभ शामिल है। अंतरिम बजट 1998-99 के अनुसार यह लगभग 56% है।

(ग) और (घ) केवल प्रशासनिक खर्चों के संबंध में, सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। बहरहाल, 1981 में सरकार ने एक उच्चधिकार प्राप्त समिति, अर्थात रेल सुधार समिति, की स्थापना की थी, जिसने रेलों के संबंध में एक व्यापक अध्ययन किया था और कार्मिक रेल कार्य प्रणाली के अनेक पहलुओं पर रिपोर्टे प्रस्तुत की थी। इसके अलावा, समय-समय पर रेलों के भीतर, जब कभी अपेक्षित होता है, अध्ययन किए जाते है।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: As per the statement which has been laid on the Table of the House, the Minister has accepted my views that 22 per cent of the total amount spent by the Railways is spent on fuel and operational areas connected with fuel. He has also accepted that 54 per cent of the total expenditure is being spent on administrative expenditure. On the one hand there are expectatitjns and on the other hand something is being discussed in the air. The Government and the hon. Minister are thinking of diverting the subsidy from freight traffic to passenger traffic.

That is, subsidy given to passenger traffic from freight traffic earnings would help in cheaper cost to the travellers. Now you are also trying to increase in a phased manner the fares. But you are also trying in other areas to raise more funds. You also accept that 54 per cent of the total amount is spent on staff and other administrative expenses alone. So, what are the reasons so to why you are not thinking of ways to reduce the expenditure on administrate side? Secondly, what are the difficulties which are you facing in the sphere of making more investment for the development of railways?

श्री नीतिश कुमार : सर, उत्तर में यह बतलाया गया है। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर की बात की है वह 8 प्रतिशत के आसपास या इससे कुछ ज्यादा है, लेकिन जो पूरे स्टाफ पर एक्सपेंडीचर हैं वह इंटरिम बजट 1998-99 के हिसाब से लगभग 56 प्रतिशत है परन्तु यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेडीचर जो जोनल रेलवे में या डिवीजनल में या और भी इस तरह के मेनेजमैंट का कार्य है उसमें लगे हुए लोगों के खर्चे को ऎडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर माना जाता है। लेकिन बाकी जो स्टाक कास्ट है यह आपरेशन में लगे हुए लोग हैं या प्रोडक्शन में लगे हुए लोग हैं इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर नहीं माना जा सकता। अभी रेलवे की जो स्थिति है उसके हिसाब से 8 प्रतिशत से कुछ ज्यादा टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर है जो बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है और जो स्टाफ कास्ट है वह स्वाभाविक है। चूंकि रेलवेज में आदमियों की जरुरत ज्यादा होती है और यह इस प्रकार का आर्गनाइजेशन है कि इसको मेनेज करने के लिए, इसको आपरेट करने के लिए और इससे जुड़ी हुई प्रोडक्शन युनिट्स में जो लोग काम करते हैं वह सब चूंकि प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, आपरेशन से जुड़े हुए हैं इसलिए उनके वेतन क हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेडीचर नहीं मान सकते । इसलिए उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर कम है । लेकिन पूरा जो वेतन का बिल, आप मान सकते है, वेज बिल इन्टरिम बजट के हिसाब से लगभग 56 प्रतिशत है, इसमें कुछ जो वृद्धि हुई है वह पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण हुई है। अब ऎसी स्थिति में बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों को या काम करने वाले लोगों को रेलवे सिस्टम से हटाना सम्भव नहीं है। रेलवे के आपरेशन्स रिक्वायमेंट को देखते हुए लेकिन जैसे ही टेक्नालोजीकल अपग्रेडेशन होता है तो स्वाभाविक तौर पर कम लोगों की जरुरत पड़ती है। चूंकि रेलवे का काम बढ रहा है। चाहे ज्यादा यात्रा करने वाले लोग हों, चाहे ज्यादा ट्रेनें चलाई ज रही हो, सब चीज की रिक्वायरमेंट बढती जा रही है। इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है लेबर फोर्स की या वर्क फोर्स की वह प्रोडक्टिविटी बढेगी टेक्नालोजीकल अप-ग्रेडेशन से । यही स्थिति है।

श्री बलवना सिंह रामूवालिया : सर, अभी मंत्री जी ने कहा कि 8 प्रतिशत व्यय है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर

में है, लेकिन वह मान गए कि 56 प्रतिशत भी है, टोटल मिलाकर जो सभी काम करने वालों को दिया जाता है। मैं दो मुद्दे आपके माध्यम से सदन के सामने मंत्री जी से पूछ रहा हूं। पहली बात जो सोशल आब्लीगेशन की है। क्या यह सच है कि दूसरे देशों में 30-40 प्रतिशत फंड सोशल ऑब्लीगेशन पर खर्च होता है जबकि हमारे यहां रेलवेज में यह केवल 18 प्रतिशत होता है?

दूसरे, चूंकि हम इन्फ्रास्ट्राक्चर बिल्ड नही कर रहें है और सारी धनराशि एम्पलाईज पर, काम करने वालों पर जा रही है इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर नही बढ़ रहा है और जहां तक फ्रेट ट्रेफ़िक की बात है वह कभी रेलवे के पास 70 प्रतिशत था और आज वह घटते-घटते 35 प्रतिशत रह गया है। क्या आप कोई उपाय कर रहे है? क्योंकि सबसे ज्यादा आमदनी फ्रेट ट्रेफ़िक से होती है फ्रेट ट्रेफ़िक से आमदनी बढ़ाकर ,एम्पलाइज का खर्चा घटाकर, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर, जो फ्रेट ट्रेफिक रेलवे से रोड की तरफ डाइवर्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे है?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय कल ही इस सदन में स्टेटस पेपर प्रस्तुत किया गया है और पारसी दूसरे सदन में रखा गया था। उस स्टेटस पेपर में रेलवे की आज की पूरी स्थिति की चर्चा की गई है। जो आपने बताया है कि कुल मिलाकर फ्रेट ट्रेफिक रेलवे से रोड की तरफ डाइवर्ट हो रही है, उसके कारणों को भी गिनाया गया है और रेलवे के सामने जो कठिनाई है उसको भी रखा गया है। जहां तक उपाय करने का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर पर अंकुश लगाने के लिए मितव्ययिया का रास्ता अख्तियार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके साथ ही जिस क्षेत्र में जहां तक संभव हो खर्च में कटौती की जा रही है। आमतौर पर एक शिकायत होती थी कि बहुत बड़ा खर्च विज्ञापनों और समारोहों पर किया जाता है। नई सरकार के आने के बाद उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। आवभगत, तामझाम इन सब चीजों पर खर्च बहुत कम किया जा रहा है। वह बात सही है कि अगर पूरे ट्रम में देखें या रुपए के ट्रम में देखें ताकि इसका बहुत बड़ा असर जाता है और हर स्तर पर मितव्ययिता का एक वातावरण बनेगा, यह तो एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि रेलवे जिस ढ़ंग की संस्था है, जिस ढ़ंग का संगठन है कि इसमें लोगों तो लागेंगे। आप इससे न घबराएं कि 56 प्रतिशत स्टाक कॉस्ट है । ये निठल्ले बैठने वाले लोग नहीं है। अब धीरे-धीरे रेलवे में काम करने वाले लोगों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। एक कर्मचारी से एक से अधिक किस्म के काम लिए जा रहे हैं और आपग्रेडेशन के जरिए, टेक्नॉलोजिकल अपग्रेडेशन के जरिए उनकी प्रोडेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है जो कि निंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए मैं माननीय सदन और माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

इसी के साथ मैं एक आग्रह जरुर करुंगा कि जो रेलवे की स्थिति है, जो रेलवे की कठिनाइयां हैं स्टेटस पेपर में, उसका उल्लेख किया गया है। इस पर सबको सोचना चाहिए कि रेलवे की हालत बेहतर कैसे हो उसमें जो सवाल सामने रखे गए हैं उन पर सबको खुले मन से विचार करना होगा।

श्री बरजिन्दर सिंह : महोदय, मंत्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर और स्टाफ कॉस्ट की बात कही है और उन्होंने रेलवे स्टेटस पेपर में पांच साल में 10 प्रतिशत कॉस्ट कम करने के लिए कहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से मुद्दे है, कौन-कौन से मुद्दे है, कौन-कौन सी चीजें है जिन पर इफेक्टिवली ये खर्च कम करने के योग्य हो सकें?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, रेलवे एक्सपेंड करता जा रहा है, सिस्टम एक्सपेंड करता जा रहा है। हर साल नई लाइनें बिछाई जा रही है, लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है, गेज कनवर्जन को रहा है। इससे मांग बढ़ रही है, न सिर्फ यात्रा के क्षेत्र में बल्कि माल-यातायात के क्षेत्र में भी ज्यादा माल जी ढलाई रेलवे कर रही है। इस प्रकार जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें जो वर्क फोर्स है उसकी प्रोडेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी स्तर से धीरे-धीरे टेक्नॉलाजीकल अपग्रेडेशन करें और उनकी प्रोडेक्टिविटी बढ़ाएं तो जो आज परसन्टेज है वह धीरे-धीरे घटेगी।

PROF. RAM KAPSE: The Hon. Minister has placed before the House a Status Paper yesterday and he has mentioned that this is a commercial enterprise and we will have to run it like a commercial enterprise. On page No. 28, on this point he has mentioned staff cost as the major component of working expenses today, i.e. 56 per cent, it is imperative that if the Railways have to retain their pre-eminence in the transport sector, this will have to be reduced. Then, again, in the third paragraph he has said, considering the present financial situation of the organisation there is an urgent need to reverse this trend. The trend is, the percentage of staff cost to ordinary working expenses has increased. This is his Status Paper and he has already mentioned that his intention is to see to it that on staff management the expenditure is lowered. So I would like to ask the Minister as to what his plans are to lower the expenditure on staff as on today,

श्री नीतिश कुमार : महोदय, जैसा मैंने पहले कहा योजना रेलवे की यही है कि हम धीरे-धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर उसके असर को कम करते चले जाएं, यही योजना है। लोगों को रेलवे सिस्टम से हटाकर हम कोई काम नहीं कर सकते है। लेकिन जैसे ही अनेक क्षेत्रों में उच्च स्तर की टेक्नॉलाजी आती चली जा रही है। तो उसमें कई प्रकार के काम की जरुरत नहीं पड़ेगी और इस सिलसिले में जो काम में लगे हुए लोग है, धीरे धीरे से या तो दूसरे काम में

जायेंगे या वे अपने काम से मुक्त होते चले जायेंगे। यह एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस तरह से हम लोग इसको करना चाहते हैं न कि एक झटके में लेबर फोर्स की संख्या को वर्क की संख्या जो है, उसको हटा देना चाहते हैं लेकिन यह बात गलत भी है क्योंकि आज की तारीख में जिस प्रकार का रेलवे सिस्टम है, उसमें लगे हुए लोग अपने दायित्व को भली भांति निभा रहे है और उनकी आवश्यकता भी है।

सैयद सिब्ते रजी : सर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि रेलवे का बहुत जबर्दस्त तरीके पर पिछले कई वर्षों में एक्सपेंशन हुआ है। नयी लाइनें बिछाई है, कन्वर्शन हुआ है। लेकिन मूलभूत जो यात्री है उनकी सुविधाओं में तो कमी आई है। आपने अपने जवाब में कहा है किसन 1981 में एक कमेटी अप्वाइंट की गई थी जिसने रिफार्म का आस्पेक्ट देखा था। मैं, मान्यवर माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को अडाप्ट कर लिया था और अगर अडाप्ट कर लिया था तो उस पर अब तक इधर वाइज क्या ऐक्शन टेकन हुआ है, इसको क्या आप बताने की कृपा करेंगे? साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं उनको कम करके यात्रियों को सुविधाओं को बढाने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं क्योंकि साधारण पैसेंजर को रेलवे स्टेशनों पर पानी तक

नहीं मिलता है और 10-12 रुपये में पानी की बोतल मिलती है जिसको जो गरीब यात्री है, साधारण यात्री है वह अफोर्ड नहीं कर सकता है?

†**شری سید سبط رضی:** سر۔ माननीय मंत्री जी نے کہا کہ ریلوے کا بہت زبردست طریقہ پر پچھلے کئی ورشوں میں ایکسپینشن ہوا ہے۔نئی لائنیں بچھائی ہیں۔کنورجن ہوا ہے۔ لیکن مول بھوت جو یاتری ہیں انکی سویدھاؤں میں تو کمی آئی ہے۔ آپنے اپنے جواب میں کہا ہے کہ سنہ ۱۹۸۱ میں ایک کمیٹی اپائنٹ کی گئی تھی جس نے ریفارم کا آسپیکٹ دیکھا تھا۔ میں माननीय मंत्री जी سے جاننا چاہونگا کہ کیا سرکار نے اس رپورٹ کو اڈاپٹ کرلیا تھا اور اگر اڈاپٹ کر لیا تھا تو اس پر اب تک ایئر وائز کیا ایکشن ٹیکن ہوا ہے۔ اسکو کیا آپ بتانے کی کرپا کرینگے۔ ساتھ ہی یا تریوں کی سویدھاؤں کے بارے میں جوایڈ منسٹریٹیوں خرچ ہیں انکو کم کرکے یا تریوں کی سویدھاؤں کو بڑھانے کیلئے آپ کیا کارروائی کرنے جا رہےہیں۔کیونکہ سادھارن پسنجر کو ریلوے اسٹیشنوں پر پانی تک نہیں ملتا ہے اور دس بارہ روپیہ میں پانی کی بوتل ملتی ہے جسکو جو غریب یاتری ہے۔ سادھارن یاتری ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, कुछ बातों के उत्तर के लिए उन्हें कुछ क्षण इंतजार करना चाहिए। रेलवे बजट प्रस्तुत होने वाला है।

जहां तक रेलवे रिफार्म कमेटी का सवाल है, 1983 की इसकी रिपोर्ट है और कई वैल्यूम्स में उनकी रिपोर्ट है और लगभग 2000 रेकमन्डेशंस रेलवे ने स्वीकार कर ली है और उस पर अमल करना भी शुरु कर दिया है। लेकिन इसमें कई रेकमन्डेशंस है, जैसी कि मुझे जानकारी दी गई है। उनको एडाप्ट करना संभव नहीं है। यह बहुत पुरानी रिपोर्ट है। लेकिन इसके अलावा भी रेलवे सिस्टम में निरन्तर एक प्रयास चलता रहा है, एफिसियेंसी बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का और इस सिलसिले में अलग-अलग समय पर अलग अलग काम होते रहते है। अगर माननीय सदस्य रेलवे रिफार्म कमेटी की सारी अनुशंसाओं का उल्लेख करना चाहेंगे तो पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरी समझ से जरुर उपलब्ध होगी, लेकिन अगर वह चाहेंगे तो फिर नये सिरे से हम उस रिपोर्ट को संसद के पुस्तकालय में फिर से उपलब्ध करा सकते है। वैसे मैं समझता हूं कि यह जरुर वहां उपलब्ध होगी।

†[]Transliteration in Arabic Script.